



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

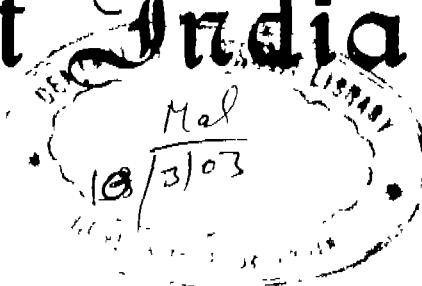
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]
No. 224]नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क मानविक्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

अंतिम जांच परिणाम

विषय: यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया के मूल से अथवा वहाँ से नियांसित एकेलिक फाइबर के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच—
अंतिम जांच परिणाम

सं. 42/1/2001-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं
वसूली और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अधीन।

क प्रक्रिया

2 जांच के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है-

(१) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारीभी कहा गया है) ने उपर्युक्त नियमों के
अंतर्गत घरेलू उद्योग की तरफ से एकेलिक फाइबर मैन्यूफैक्चररस फोरम नई दिल्ली से एक लिखित

याचिका प्राप्त की है, जिसमें यूके, जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यात किए गए एक्रैलिक फाइबर (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है।

(ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम 5(क) के उपनियम (5) के अनुसार जांच प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई से पूर्व भारत स्थित यूके, जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया के दूतावासों को याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई याचिका की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया है।

(iii) प्राधिकारी ने उनके पास उपलब्ध सूचना एवं साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया।

(iv) प्राधिकारी ने 28 अगस्त 2001 को एक सार्वजनिक नोटिट जारी किया जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची । के शीर्ष 5501.300 और 5503.30 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई।

(v) प्राधिकारी ने यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच पर 7.12.2001 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के बारे में अधिसूचित किया था और हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार इस गजट के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित रूप में भेजने का अनुरोध किया था।

(vi) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिससे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

(vii) प्राधिकारी ने यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया के नई दिल्ली दूतावासों और भारत में यूरोपियन कमीशन के प्रतिनिधि मंडल को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति भी अग्रेषित की थी।

(viii.) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकार को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 27.03.02 को अवसर प्रदान किया था। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। पार्टियों से प्रतिपक्षी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उसका खंडन, यदि कोई हो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(ix.) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी।

(x.) प्रारंभिक जांच परिणामों, जिन्हें अधिसूचित किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकाशित किया गया है, की घोषणा से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तकर्ता को संक्षिप्तता की दृष्टि से इसमें दोहराया नहीं गया है। परन्तु हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाद में दिए गए तकर्ता पर इन जांच परिणामों में उचित कार्यवाही की गई है।

(xi.) उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधारों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8.8.02 के प्रकटन विवरण-पत्र के तहत बताया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है।

(xii) प्राधिकारी ने उपभोक्ता उद्योग संगठनों को एक-एक करके सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया।

(xiii) इस जांच में 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि शामिल है।

(xiv) इस अधिसूचना के *** भाग में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दो गई सूचना शामिल है और जिनपर प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उसी रूप में विचार किया गया है।

ख. याचिकाकर्त्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच

3. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लाइस दिए गए विचारों पर प्रारंभिक जांच परिणामों में दीर्घ प्रकटन विवरण-पत्र में भी चर्चा की गई है। जिन विचारों पर प्रारंभिक जांच परिणामों और प्रकटन विवरण पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण के जवाब में उठाए

गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहां कहीं उचित समझा गया है, नीचे दिए गए संगत-पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रीलिक फाइबर है। एक्रीलिक फाइबर सिन्थैटिक पॉलिमर की एक लम्बी शृंखला है जो 90 % एक्रीलोनाइट्रिल इकाइयों से बना है। एक्रीलिक फाइबर एक्रीलिक स्टैपल फाइबर, एक्रीलिक टॉव अथवा एक्रीलिक टॉप हो सकता है। सभी तीनों रूप इस जांच की विषय-वस्तु है। एक्रीलिक फाइबर अध्याय शीर्षक 55.01 और 55.03 में वर्णीकृत है। उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत छ: संख्या स्तर पर 5501.30 और 5503.30 के अधीन और आईटीसी के अंतर्गत 5501.3000 और 55.30.3000 के अधीन वर्णीकृत है। मौजूदा जांच विचाराधीन उत्पाद के संबंध में थी चाहे उसके आयात का वर्गीकरण कोई भी हो। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र में इसकी किसी प्रकार से बाध्यता नहीं है। प्रकटनों के जारी होने के बाद लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी जांच के लिए एक्रीलिक फाइबर टैब और टाप पर विचार कर रहे हैं और सीमाशुल्क प्राधिकारी समान पद्धति पर विचार नहीं करते हैं। एसोसिएशन पुनः निवेदन करती है कि एक्रीलिक फाइबर के तीनों प्रकारों पर विचार करने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी इस बात की भी पुष्टि करे कि एक्रीलिक फाइबर एक्रीलिक टॉव और एक्रीलिक टॉप हो सकता है। इस समय तक ऐसा किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल एक्रीलिक फाइबर तक सीमित किया जाता है। प्राधिकारी ऐसा पाते हैं कि लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन ने जांच के प्रारंभ होने पर अथवा प्रारंभिक जांच परिणामों के तैयार होने के बाद अथवा मौखिक सुनवाई के बाद अपने किसी भी निवेदन में विचाराधीन उत्पाद के विषय में कोई तर्क नहीं दिया था ताकि प्राधिकारी द्वारा उनके द्वारा किए गए निवेदन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार हेतु अथवा खण्डन करने के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे। अतः प्राधिकारी के विचार में ये तर्क बहुत देर से किए गए हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए तर्क स्वीकार्य नहीं है और विचाराधीन उत्पाद के संबंध

में अरंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

5. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि इसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल से अथवा जांच का उत्तर देने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार, ने ऐसा कोई विवाद नहीं किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर और धरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित एक्रीलिक फाइबर एक समान नहीं है ।

अतः प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि धरेलू उद्योग द्वारा निर्मित एक्रीलिक फाइबर विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

(घ) धरेलू उद्योग:

6. एक्रीलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स फोरेम, नई दिल्ली द्वारा धरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर की गई है । भारत के निम्नलिखित एक्रीलिक फाइबर उत्पादकों ने मौजूदा पाटनरोधी जांच में भाग लेने के लिए विशेष रूप से सहमति प्रदान की है ।

क. इंडियन एक्रीलिक्स लिमिटेड

ख. कोन्सोलिडेटेड फाइबर एंड कैमिकल्स लिंग

ग. पशुपति एक्रीलॉन लिमिटेड

उपर्युक्त कंपनियों ने मौजूदा जांच के लिए सभी अपेक्षित सूचना दी है और सूचना और सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है ।

7. लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन के विचार - लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन ने यह तर्क दिए हैं कि धरेलू उद्योग के लिए उत्पादन आंकड़े ठीक नहीं हैं, जैसाकि इसके सभी भारतीय कर्ताईकार के उत्पाद शामिल नहीं किए गए हैं ।

भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन के विचार:

8. भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन ने यह तर्क दिया है यद्यपि धरेलू उद्योग के अपेक्षित प्रतिशत हिस्से द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर की गई हो तो भी सम्मिलित रूप से धरेलू उत्पादकों के लिए आयातों के प्रभाव का अध्ययन करना होता है । धरेलू उद्योगों द्वारा अपनाया गया चुनने का तरीका उचित और उपयुक्त नहीं है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी ने यह पाया है कि तीन याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का 61 % है जिसमें मैरो वर्धमान एक्रीलिक लिंग का उत्पादन भी शामिल है जो संबद्ध वस्तुओं का आयातक है । कुल भारतीय उत्पादन से मैसर्स वर्धमान एक्रीलिक लिंग के

उत्पादन को घटा देने के बाद भारतीय उत्पादन में तीनों याचिकाकर्ता कंपनियों का 73.85 % हिस्सा है।

10. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग का अभिप्राय समान वर्स्तु के विनिर्माण में और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे समग्र उत्पादकों अथवा जिनका कथित वर्स्तु का सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हो, जिनमें ऐसे उत्पादक शामिल नहीं होंगे जो कथित पाटित वर्स्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ संबंधित हो अथवा वह उसके ख्वयं निर्यातक हो, तो ऐसे मामले में (ऐसे उत्पादकों को) घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता समान वर्स्तुओं के सकल भारतीय उत्पादन में बड़े हिस्से अर्थात् 50 % से अधिक के भागीदार हैं इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि उपर्युक्त नियम 2(ख) की सीमा के अर्थ के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं को "घरेलू उद्योग" समझा जाए।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन संबंधी मुद्दों की जांच।

11. **घरेलू उद्योग के विचार**

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ब्राजील, बुलगारिया, जर्मनी और यूके में ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी थी। कुछेक निर्यातकों ने प्राधिकारी को उत्तर भेजा है। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में पाया है कि निर्यातकों द्वारा भेजे गए जबाब समग्र रूप से अपर्याप्त और अपूर्ण हैं। किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई अतिरिक्त सूचना नहीं भेजी है। अतः अंतिम निर्णय के लिए निर्यातकों के जबाबों को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार पर सर्वैत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में ही प्राधिकारी द्वारा औचित्य सिद्ध किया जाएगा।

12. **भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन के विचार**

भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं:-

- (i) एक ही सौदे के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं है। यह असामान्य सौदा हो सकता है।
- (ii) ब्रसल में स्थित सी आर एफ आई एस ने यह सूचित किया है कि विशेष उत्पाद के लिए मूल्य 2.67 अमरीकी डालर है। यह सूचना अस्वीकृत नहीं की जानी चाहिए।
- (iii) जर्मनी के लिए सामान्य मूल्य 1.66 अमरीकी डालर है इसलिए यदि उचित रूप में मालूम हो जाए तो यूके में सामान्य मूल्य किसी भी स्थिति 2.67 अमरीकी डालर नहीं हो सकती। इससे घरेलू उद्योग का दावा झूठा मालूम होता है।
- (iv) जर्मनी के लिए सामान्य मूल्य एक ही सौदे के आधार पर निर्धारित किया गया है जोकि सही नहीं है।
- (v) बलगारिया के निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना पर दिशानिर्देश के रूप में विचार किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए अपनाया गया लागत का तरीका अटकलबाजी से भरा हुआ है।

- (vi) ब्राजील के संबद्ध में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने परिवहन लागत विद्युत लागत, श्रम लागत और वित्तीय लागत आदि की गणना की हैं और इसलिए सामान्य मूल्य की गणना रखीकार नहीं की जानी चाहिए ।
- (vii) निर्यात मूल्य के संबंध में प्राधिकारी ने भाड़ा, बीमा, कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा और पत्तन प्रभारों के कारण कुछ मानक समायोजन की अनुमति दी है । प्राधिकारी को इन समायोजनों के कारण वास्तविक लागत के प्रभाव पर विचार करना चाहिए ।

13. लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत निवेदन ।

- (i) सर्दभाधीन चार देशों के निर्यातकों द्वारा किए गए पाटन के संबंध में घरेलू उत्पादकों का तर्क स्वीकार्य नहीं है । क्योंकि इन देशों के उत्पादकों द्वारा वस्तुएं सामान्य मूल्य पर भेजी गई हैं । वह मूल्य जिस पर निर्यातकों ने हमारें देश के आयातकों को वस्तुएं भेजी गई है, उनके बड़े बड़े आधुनिक संयंत्रों, लागत की जानकारी और कार्यकुशलता पर आधारित है ।
- (ii) सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अकेला कोई सौदा आधार नहीं होना चाहिए । निर्यातित वस्तुओं की गुणता सामान्य एकलिक फाइबर की नहीं बल्कि बेहतर किस्म की भी होनी चाहिए ।
- (iii) सामान्य मूल्य निर्धारण परिकलित मूल्य के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए । प्राधिकारी इन देशों में भारतीय मिशन की सेवाओं का उपयोग करे ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सामान्य मूल्य

जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबत्र वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों को एक प्रश्नावली भेजी थी । प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों को यह सलाह दे कि वे प्राधिकारी को उत्तर भेज दे । निम्नलिखित निर्यातकों/निर्यातक संगठनों से जबाब प्राप्त हुए थे-

- (i) एक्रेजे यूके लि. यूके
- (ii) मै. लुकायू ऑयल कंपनी बुलगारिया
- (iii) डियूपॉट डियूशलेड होलिंडेंग जी एम बी एच एंड कंपनी केजी जर्मनी
- (iv) ड्रेलॉन जी एम बी एच वेयर वर्क जर्मनी
- (v) इंटरनेशनल रेयान एंड सिनथैटिक फाइबर्स कमेटी
- (vi) (सी आई आर एफ एस) ब्रुसल्स

इन जबाबों पर प्रारंभिक जांच परिणामो के स्तर पर उचित रूप से विचार किया गया था प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों और भारत में यूरोपियन कमीशन के प्रतिनिधिमंडल को प्रारंभिक जांच परिणामों के बारे में सूचित कर दिया था ।

15. प्रारंभिक जांच परिणामो के बाद निम्नलिखित जबाब प्राप्त हुए हैं:-

(i) मै. लुकोइल बुलगारिया ने इस बात की पुनरावृति की कि उनका भारत को एक्रेलिक फाइबर का निर्यात ग्रेड ब्रिटेन में स्थित एक व्यापारी के माध्यम से किया गया है। जिसने फाइबर्स को वास्तव में भारतीय प्रयोक्ताओं को उनके पहले उत्तर में उल्लिखित मूल्यों से अधिकतम मूल्यों पर बेचा था।

(ii) मै. एकोर्डिज यूके ने सूचित किया था वे कीमत से संबंधित विवरण भेजने की कार्यवाही कर रहे हैं। तथापि प्राधिकारी के पास निर्यातकों को भेजे गए प्रोफार्मा जिस पर निर्यातकों द्वारा ऑफर की गई वरतुओं के वास्तविक निर्यात मूल्य निर्दिष्ट किए गए थे, पर पूरा मूल्य विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, ताकि जिसके आधार पर प्राधिकारी इस विषय पर विचार कर सके।

(iii) मै. मैकीज फेसर ए जी जर्मनी में सूचित कर्य है कि उन्होंने सितम्बर 2000 में एक्रेलिक फाइबर का उत्पादन बंद कर दिया है।

(iv) ब्राजील संघ गणराज्य के दूतावास ने अपने प्रकटनों के बाद निम्नलिखित निवेदन किए हैं-

(क) जांच में ब्राजील एक हितबद्ध पक्षकार होने के नाते ऐसा दावे के साथ कहना चाहता है कि खुलासा की गई रिपोर्ट में निर्णयाधीन आवश्यक तथ्य निहित नहीं है, जो कि जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय को प्रमाणित कर दे। वे तथ्य रिपोर्ट में और 7.12.2001 को जारी की गई क्षति की प्रारंभिक अधिसूचना में शामिल नहीं है।

(ख) डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार, जिसे अब तक डब्ल्यू टी ओ करार के रूप में जाना जाता है, के अनुच्छेद 69 के अनुसार उन आवश्यक तथ्यों का निर्धारण क्षति एवं कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु की गई पाटनरोधी जांच द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 2 के अनुरूप सामान्य मूल्य निर्यातकीमत एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु प्रयुक्त पद्धति का खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसा ही संबंधित तत्वों और मूल्यों के बारे में भी किया जाना चाहिए।

(घ) उद्गम के अनुसार आयातों की मात्रा और उनके प्रभावों का संचयी मूल्यांकन सुविधानुसार प्राप्त नहीं हुआ है और न ही डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.2... 3.3 और 5.8 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों तथा राष्ट्रीय उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा से संबंधित आंकड़े ही उपलब्ध हैं।

(ङ.) उसी समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन की मात्रा के सही आंकड़े और उनके समर्थक आंकड़े तथा इसके अतिरिक्त डब्ल्यू टी ओ (वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाइजेशन) के करार के अनुच्छेद 3,4 के अनुसार क्षति निर्धारण के लिए संबंधित घटक और संगत आर्थिक संकेतक भी प्रकट किए जाने चाहिए।

(च) इससे अधिक निम्नलिखित पहलूओं के अनुसार अन्य सूचना में संगत आंकड़े शामिल होने चाहिए:-

(i) आयातों की मात्रा की तुलना में घरेलू उद्योग और राष्ट्रीय उद्योग का उत्पादन और बिक्री

(ii) भारतीय बाजार में प्रकट मांग के नमूने

(iii) संस्थापित क्षमता के उपयोगिता का विकास

(iv) मूल्य रचना

(v) उद्योग में रोजगार एवं वेतन का क्रम विकास

(vi) उद्योगीय उत्पादकता के नमूने

(vii) संस्थापित क्षमता का लाभ निवेश वापसी आन्तरिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक द्वारा पर वास्तविक अथवा संभावित नकारात्मक प्रभाव मूलधन बढ़ाने और निवेशों को आकर्षित करने में वृद्धि और क्षमता ।

— हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों, प्रतितर्कों और प्रत्युतरों के मात्र प्रस्तुतीकरण से, जैसाकि उपर्युक्त रिपोर्ट से अर्थ निकाला गया प्रतीत होता है, डब्ल्यू टी ओ के करार के अनुच्छेद 6.9 के अनुसार विशेष अनिवार्य तथ्य प्रस्तुत नहीं हो जाते हैं ।

— ब्रेजिलियन सरकार यह पुष्टि करती है कि पाटन मूल्यों से आरोपित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर क्षति के कोई लक्षण स्पष्ट नहीं हैं ।

(viii) ब्रेजिलियन दूतावास द्वारा ऐसे पुनः तर्क दिए गए हैं कि उन घरेलू कंपनियों जिन्होंने याचिका दायर नहीं है, के उत्पादन, बिक्री मूल्यों से संबंधित सूचना पर जांच प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है । अन्य कारक यथा नियोजित तकनीक के अनुसार घरेलू उद्योग की संचालन स्थिति और उपकरणों का अप्रचलन, मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की क्षमता तथा आयातों के अलावा अन्य कारकों के मूल्यांकन पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया ।

(ix) उनके निवेदनों को ध्यान में रखते हुए ब्रेजिलियन दूतावास ने इस जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

16. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के संबंध में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को दोहराया है । यूके से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली पर कोई पूरा जबाब नहीं भेजा । केवल मै. एकार्डीज यूके ने मूल्य विवरण ऑफ र किया । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित तरीके से पूरे और पर्याप्त जबाबों की अनुपस्थिति में उपरोक्त नियम 6(४) के अनुसार पर्याप्त उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूके में निर्यातों के संबंध में जांच परिणाम तैयार कर लिए हैं । प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रारंभिक जांच परिणामों हेतु जिन घरेलू बिक्री सौदों पर विश्वास किया गया था वे विशेष एक्रैलिक फाइबर से संबंधित हैं और उनके विधार

से यह यूके के संबंध में सामान्य मूल्य के लिए आधार माना⁹ जा सकता है और इसलिए यूके के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन के परिकलित मूल्य के आधार पर सुनिश्चित किया गया है जैसकि याचिकाकर्ता द्वारा सूचना दी गई है ।

17. प्राधिकारी जर्मनी से संबंधित सामान्य मूल्य पर अपने प्रारंभिक जांच परिणामों की ओर ध्यानाकर्षित किया है । प्राधिकारी के पास कोई नए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए । प्राधिकारी ने परिकलित सामान्य मूल्य संबंधित सूचना पर भी विचार किया है । प्राधिकारी ऐसा पाते हैं कि जर्मनी से किसी अन्य देश में निर्यात के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा दिए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य परिकलित सामान्य मूल्य से निम्नतर है । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से पूरा और पर्याप्त उत्तर प्राप्त न होने पर, उन्होंने उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार जर्मनी से किए गए आयातों के बारे में जांच परिणाम तैयार कर लिए हैं । तदनुसार प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य की पुष्टि करते हैं ।

18. प्राधिकारी ने बुलगारिया के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए उत्पादन के परिकलित लागत पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बुलगारिया के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से पूरा और पर्याप्त उत्तर प्राप्त न होने पर, उन्होंने उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बुलगारिया से किए गए आयातों के बारे में जांच परिणाम तैयार कर लिए हैं । तदनुसार प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है ।

19. ब्राजील से किसी भी निर्यातक द्वारा किसी भी स्तर पर कोई उत्तर नहीं आया है । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहां तक प्रकटन का विवरण के उत्तर में ब्राजील दूतावास द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का संबंध है प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना शुरू करने अथवा उसके बाद किसी निर्यातक अथवा ब्राजील सरकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किए गए थे । सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त तरीके के बारे में प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि नियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राजील के संबंध में सामान्य मूल्य पर उत्पादन की परकलित लागत के आधार पर विचार किया जाना है । यह स्थिति इस कारण है कि ब्राजील के किसी निर्यातक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सूचना भेजने में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्राजील के निर्यातकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से पूरी और पर्याप्त सूचना नहीं भेजने के कारण उक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ब्राजील के निर्यातकों के संबंध में जांच परिणाम तैयार किए हैं । तदनुसार प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है ।

20. निर्यात मूल्य

प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य निर्धारण के संबंध में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को ध्यान में रखा है । निर्यातकों की ओर से निर्यात मूल्य अथवा अनुभव समायोजनों के विषय में अधिक से अधिक

सूचना/साक्ष्य देने के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अंतः प्राधिकारी यूके जर्मनी और बुलगारिया के संबंध में निर्यात मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण की पुष्टि करते हैं। ब्राजील के संबंध में प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से निर्यात लेन देन के विषय में अधिक सूचना मांगी है। प्राधिकारी को सौदों के अनुसार और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ब्राजील दूतावास ने प्रकटन विवरण से संबंधित अपनी टिप्पणियों में ब्राजील के निर्यातकों के निर्यात मूल्यों आदि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। ब्राजील के निर्यातकों से संबंधित किसी नई सूचना के प्राप्त नहीं होने पर प्राधिकारी उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना अर्थात् डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर विश्वास करने के लिए बाध्य है और प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए यथा निर्धारित निर्यात मूल्य की पुष्टि करते हैं।

21. पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारण को विनियमित करने वाले सिद्धांत नियमावली के अनुबंध । मे निहित हैं। सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच उचित तुलना करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने व्यापार के समान रस्तर पर गणनाएं और तुलना की हैं। कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार पर निर्यात मूल्य की तुलना की गई है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन की गणना निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	देश	पाटन मार्जिन %
1	यूके	26.16%
2	जर्मनी	10.29%
3	बुलगारिया	31.37%
4	ब्राजील	186.58%

च क्षति एवं कारणात्मक संबंध

22 पाटनधारी नियमावली के नियम 11 में निम्नानुसार व्यवस्था है :—

“क्षति का निर्धारण

- विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में उत्यधिव आती है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग । इगापना में आने वाले अत्यधिक बाधा और पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों ॥ इसके प्रभाव और ॥ इसुआ के घरेलू उत्पादकों पर आयता का परिणामी प्रभाव - रामेत रागा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-॥ मे निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार करेंगे । ”

23. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-॥ मे उल्लिखित क्षति के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में यह उपबंध किया गया है कि-

(क) क्षति के निर्धारण में इन दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी:- (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु की घरेलू बाजार कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव ।

(ख) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा समग्र रूप में पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । नियम-18 के उप-नियम (क) में यथा-उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभावों के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमतों में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से अन्यथा काफी हव तक कीमतों में कमी आयी है अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोका गया है जो अन्यथा काफी हव तक बढ़ गयी होती ।

24. घरेलू उद्योग की विचार

(i) संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशों से पाटन के कारण जांच अधिक के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जिसकी या तो जांच चल रही है या पाटनरीधी शुल्क इस पर पहले से ही लागू है ।

अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को मौजूदा शुल्क और अन्य देशों के विरुद्ध चल रही जांच के परिमेय में देखा जाना चाहिए ।

(ii) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, जो कि 1999-2000 के दौरान बढ़ रही थी, जांच अधिक में कम हो गई ।

(iii) कीमत कटौती को स्तर के मद्देनजर यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों के साथ समझौता नहीं करता तो इसकी बिक्री में और गिरावट आ सकती थीं ।

(iv) एक के बाद दूसरे देशों जिनमें संबद्ध देश भी शामिल हैं, द्वारा एक्रिलिक फाइबर का पाटन जारी रखने के कारण घरेलू उद्योग को साल-दर-साल घाटा हो रहा है ।

(v) संबद्ध देश से आयात का बाजार हिस्सा काफी अधिक है । इस हिस्से में इन वर्षों में वृद्धि हुई है ।

(vi) कर्मचारियों की संख्या घटने के बावजूद भी तेजी से उत्पादन घटने के कारण जांच अधिक के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पदकता में गिरावट आयी है ।

(vii) अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को अपने निवेश पर होने वाली प्राप्ति ऋणात्मक ही रही है ।

(viii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए भारी घाटे के कारण इस अवधि में निवेश पर प्राप्ति में काफी गिरावट आई है ।

(ix) उत्पादन में गिरावट के कारण जांच अवधि में क्षमता उपयोग भी काफी गिरा है ।

(x) अनेक देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से बहुत कम होने के कारण कीमत में भारी कटौती हुई है ।

(xi) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम होने के कारण कीमत में भारी कमी और मंदी आयी है ।

(xii) संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है अपितु बहुत अधिक भी है ।

(xiii) 98-99 में नकदी प्रवाह नकारात्मक था, जो 99-00 में सकारात्मक हो गया । किन्तु 2000-01 में नकदी प्रवाह पुनः नकारात्मक हो गया ।

(xiv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में कमी किए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास रस्टॉक का स्तर तेजी से बढ़ा है ।

(xv) मौजूदा विनियमों के कारण घरेलू उद्योग के पास कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ।

(xvi) निर्धारित लागतों के प्रभाव को कम करने के एक प्रयास के रूप में अङ्गचनों को दूर करके घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है । किन्तु इससे भी घरेलू उद्योग को अपना घाटा कम करने में कोई मदद नहीं मिली है ।

(xvii) घरेलू उद्योग के घटकों को काफी कठिनाइयों के साथ कुछ समय पहले वित्तीय पुनर्गठन करना पड़ा था । निरन्तर घाटे के कारण वित्तीय संरक्षाएं घरेलू उद्योग को निधियां उधार नहीं दे रही हैं ।

(xviii) बुल्लारिया, ब्राजील, जर्मनी और यू.के. से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

(xix) अंतिम शुल्क की सिफारिश भी केवल अमेकी डालर में (नियत राशि में) की जाए ताकि विनिमय देश में परिवर्तन होने से संरक्षण की मांग में कमी न आए ।

25. इंडियन स्पेनर्स एसोसिएशन के विचार ।

(i) क्षति को समूचे घरेलू उद्योग के लिये देखा जाए न कि केवल याचिकाकर्ताओं के लिये ।

(ii) घरेलू उद्योग को सभी उत्पादकों के बारे में सूचना देना चाहिए । छोट कर चुनने की विधि न्यायपूर्ण और उचित नहीं है ।

(iii) वस्तु आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है ।

(iv) क्षमता और उसके उपयोग में वृद्धि हुई है अतः घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

(v) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि विक्रय मूल्य 41 प्रतिशत तक बढ़ा है ।

(vi) न तो कोई पाटन हुआ है और न ही कोई क्षति हुई है ।

(vii) यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है तो उसका कारण लागत बोध का अभाव, उत्पादन की अपर्याप्त मात्रा, अनु० और विकास की कमी लथा खराब कार्यालय है ।

26. लुधियाना स्पेनर्स एसोसिएशन के विचार -

(i) हालांकि हम देश में एक्रिलिक फाइबर के सबसे बड़े उपभोक्ता है, फिर भी अनितम शुल्क लगाने से पूर्व हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया ।

(ii) इस समय 14 देशों पर पाटन रोधी शुल्क लग रहा है । इतने अधिक स्रोतों से किसी भी अन्य वस्त्र उत्पाद पर पाटन रोध शुल्क नहीं लगता है ।

(iii) यह घरेले उद्योग द्वारा अपने कुप्रबंधन, और अकुशलता पर पर्दा ढालने का एक प्रयास है तथा इसके अंतिम उद्देश्य भारतीय बाजार में एकाधिकार प्राप्त करना मात्र है ।

(iv) घरेलू उद्योग के उत्पाद संबंधी आंकड़े ठीक नहीं हैं क्योंकि इनमें सभी भारतीय उत्पादकों की उत्पादन मात्रा सम्मिलित नहीं की गई है ।

(v) पिछले साल की तुलना में उद्योग का उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ा है ।

(vi) यदि कोई क्षति हुई है तो उसका कारण गुजरात में आए तुफान और भूकंप है ।

(vii) बजट में सीमा शुल्क घटाये जाने के कारण क्षति हुई न कि आयातों के कारण ।

(viii) किसी भी घरेलू उत्पादक ने अपने तुलन पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि नये स्रोतों से पाठन के कारण उसका लाभ कम रहा है ।

(ix) उद्योग में पुरानी और दिनातीन मशीनें लगी हुई हैं जिसकी वजह से उद्योग को क्षति हो रही है ।

(x) यह उद्योग वर्तमान मांग और भावी मांग पूरा करने में सक्षम नहीं है ।

27. मैसर्स ल्युकोइल, बुल्गारिया के विचार

प्रारंभिक जांच के परिणाम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा बाजार हिस्सा केवल 3 प्रतिशत है जिससे भारतीय उत्पादकों के हिततों पर असर पड़ना संभव नहीं है । न ही इससे बाजार की कीमते प्रभावित हो सकती हैं ।

प्राधिकारी द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच -

28. क्षति के विश्लेषण के बारे में प्राधिकारी अपने प्रारंभिक जांच परिणामों का स्मरण करते हैं । घरेलू उद्योग ने क्षति के निर्धारण से संबंधित विभिन्न आर्थिक कारकों / संकेतकों की सूचना लाभ बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्राप्ति, क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेले कीमतों, लाभ प्रदत्ता, पूजी निवेश पर प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारक, नक्दी प्रवाह रोजगार, मजदूरी पर प्रभाव आदि । अतिम निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में उपर्युक्त संकेतकों को ध्यान में रखा है । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् घरेलू उद्योग, नियातकों इंडियन स्पेनर्स एसो लुधियाना स्पिओ एसो और ब्राजील दूतावास द्वारा किये गये अनुरोधों की जांच की है । प्राधिकारी का विचार है कि इस जांच के लिये घरेलू उद्योग के संबंध में नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार सभी संगत संकेतकों की जांच की गई है । यद्यपि प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित सभी मापदंडों की जांच की है तथापि कुछ ऐसे मापदंडों, जो क्षति दर्शाते हैं, पर नीचे विस्तार से चर्चा की जा रही है:-

29. जहां तक आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान और पूर्ववर्ती वर्षों में किये गये निर्यात की मात्रा संबंधी सूचना की जाँच की है। जांच अवधि दौरान चारों संबद्ध देशों से कुल आयात 4195 मीट्रिक टन का हुआ था। वर्ष 1999-2000 में यह आयात 2469 मीट्रिक टन और 1998-99 में 3739 मीट्रिक टन (लीजी0आई0 एसो10 आंकड़ों के अनुसार) हुए थे। इन आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 1998-99 में 3.35%, 1999-2000 में 2.18% और 2000-01 में 3.73% रहा था। यदि पिछले साल 1999-2000 से तुलना की जाए तो पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान इनका बाजार हिस्सा काफी बढ़ा है। किन्तु मात्रा की दृष्टि से जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात पिछले वर्ष की तुलना में 69% अधिक हुआ है। यद्यपि बाजार हिस्से में हुई यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है तथापि ध्यान देने योग्य है और समग्र रूप में जो आयात बढ़ा है वह घरेलू उद्योग के लिए खतरे का द्योतक है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि समग्र रूप में पारित आयातों में वृद्धि हुई है।

30. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समानवस्तु के मूल्य के तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुँच कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति से की है और यह पाया है कि पाटित आयातों से कीमतों में पर्याप्त कटौती हुई है। आयातों की पहुँच कीमत को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम पाया गया है। आयातों से घरेलू बाजार की कीमतों में पर्याप्त कमी/हास हो रहा था क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उचित आय प्राप्त करने के लिए अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाने में असमर्थ रहा है।

31. उत्पादन में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि के दौरान गिर कर 84.03% हो गया जो कि 1999-2000 में 93.07% था। जांच अवधि के दौरान तीनों याचिकाकर्ता कम्पनियों की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ गयी थी। किन्तु जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में याचिकाकर्ता कंपनियों के कुल उत्पादन में गिरावट देखी गयी। याचिका का समर्थन करने ली अन्य दो कंपनियों, जिन्होंने वर्तमान जांच में माग लिया, के उत्पादन में शायद जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई होगी। इण्डिन स्पिनर्स एसोएएशन का यह तर्क है कि जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता कंपनियों का भाग 61% है अर्थात् जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में उनका योगदान काफी अधिक है और उपर्युक्त नियम 2(ख) के अनुसार उन्हें "घरेलू उद्योग" माना गया है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि उक्त क्षति उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण हुई है।

32. वर्ष 1999-2000 तक घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा बढ़ रही है। किन्तु जांच अवधि के दौरान बिक्री मात्रा घट कर 59119 मीट्रिक टन रह गयी जो 1999-2000 में 70591 मीट्रिक टन थी। अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 16.25% घट गयी है। इसके अलावा, स्वदेशी उद्योग अपना माल इतनी कम कीमत पर बेच रहे हैं कि उन्हें अपनी उत्पादन लागत भी नहीं मिल रही है।

33. . पिछले कुछ वर्षों से, एक के बाद एक विदेशी राष्ट्रों से, जिसमें संबद्ध देश भी शामिल हैं, इस उत्पाद का पाटन होने के कारण स्वदेशी उद्योग लाभ नहीं कमा पा रहा है। घरेलू उद्योग की हानि जांच अवधि में तेजी से बढ़ी है, 1997-98 में यह -100 (सूचकांकित) थी जोकि जांच अवधि में - 373 (सूचकांकित) रह गयी है।

34. मजदूरों की संख्या में कमी होने के बावजूद भी उत्पादन में तेजी से गिरावट के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति मजदूर उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

35. इस अवधि में घरेलू उद्योग को हानि होने के कारण निवेश पर आय भी कम हुई है। अनेक स्रोतों पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी घरेलू उद्योगों के लिए निवेश पर आय नकारात्मक ही रही है।

36. 98-99 में नकदी का प्रवाह नकारात्मक था जो 99-00. में सकारात्मक हुआ। किंतु जांच अवधि में यह पुनः नकारात्मक हो गया।

37. घरेलू उद्योग का उत्पादन कम होने के बावजूद भी पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसका स्टॉक बढ़ा है।

38. निरंतर वित्तीय हानि और नकारात्मक नकदी प्रवाह के कारण घरेलू उद्योग को रोजगार में कटौती करने पर बाध्य होना पड़ा है।

39. लागू नियमों के कारण घरेलू उद्योग को मज़दूरी बढ़ानी पड़ रही है जिससे लाभ और प्रभावित हुआ है।

40. जांच अवधि के दौरान स्थिर लागत घटाने की दृष्टि से अड़चने दूर करके क्षमता बढ़ा कर भी घरेलू उद्योग को कोई मदद नहीं मिली है।

41. कुल मिलाकर उपर्युक्त सभी मानदंड यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है।

42. क्षति का संचयी मूल्यांकन

अनुबन्ध- II (iii) के अनुसार यदि एक से अधिक देशों से होने वाले उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करने के बाद ही ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में प्रमाणित डंपिंग का मार्जिन 2% से अधिकम है जो निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है तथा प्रत्येक देश से होने वाले आयात की मात्रा समान वस्तुओं के आयात का 3% है और (ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित सामान तथा वैसे ही

घरेलू सामान के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है। प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के मामले में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश के आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक है। प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि घरेलू तौर पर उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करना उचित होगा और यह पाया है कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण क्षति का संचयी प्रभाव पड़ा है।

43. घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु की क्षति रहित कीमत निर्धारित करते समय, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तु बनाने वाले उद्योग के लिए साधारणीकृत उपभोग मानदंड को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की ईष्टप्राप्त लागत पर विचार किया। इसके अलावा क्षति मार्जिन निकालते समय भी, उचित बिक्री या क्षतिरहित कीमत तय करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार किया। क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की गहराई से जांच की थी। क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी ने कच्चे माल और सुविधाओं का उपयोग, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गये खर्च जैसे संगत कारकों का उचित विश्लेषण किया।

कारणात्मक संबंध

44. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II के नियम (iv) में यह व्यवस्था है कि:

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और संकेतकों की जांच शामिल होगी जोकि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, निविष्ट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से आयात अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह स्टॉक पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि जूँ क्षमता।”

45. प्राधिकारी ने सभी संबद्ध सूचकों की जांच कर ली है। संबद्ध देशों से पाटित आयात की मात्रा वास्तविक रूप में बढ़ी है। पाटित आयात से घरेलू उद्योग के उत्पाद की कीमतों पर मूल्य कटौती का प्रभाव बहुत अधिक है। पाटित आयात की पहुंच भूलों के कारण घरेलू उद्योग को अपना माल इतनी कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है उसे उसकी लागत भी वसूल नहीं हो रही है। पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की उचित बिक्री कीमत वसूल नहीं कर पा रहा है, परिणामतः उसे वित्तीय घाटा हो रहा है। घरेलू उद्योग को ज्ञानि हुई है। पूंजी निवेश पर प्राप्ति नकारात्मक हो गयी है। उद्योग में नकदी का “नाह नकारात्मक हो रहा है। हितबद्ध कुछ पार्टियों ने ऐसे अपोषणीय दावे किये हैं कि मरेलू विकास तथा अद्वितीय आदि जैसे अन्य कारणों से हानि हुई है। प्राधिकारी को ये तक बेजान लगे हैं। अतः प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण ही घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इन बातों महे नज़र क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणामों की पुस्ति करते हैं।

छ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

46. कुछ आयातकों और उपयोक्ताओं ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाते समय एक्रिलिक फाइबर उपयोग करने वालों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए । उन्होंने एक्रिलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि आयात का खतरा स्थानीय उत्पादकों की कीमतों को बढ़ने से रोकता है ।

47. इस संदर्भ में प्राधिकारी अपने प्राथमिक जांच परिणामों पर पुनः बल देते हैं जिसमें यह कहा गया था कि सामान्यतया पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे सामान्यतया घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः उत्पन्न करना है जो देश के सामान्य हित में है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एक्रिलिक फाइबर के उपयोग से विनिर्भित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । तथापि पाटनरोधी उपयोग से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपयोगों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का लास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपयोगों से संबद्ध देशों से आगात मिल्जी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपभोक्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा । उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के हो या इससे अधिक खर्च सकेंगे ।

ज अंतिम निष्कर्ष

48. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि:-

- (i) संबद्ध देशों द्वारा भारत को एक्रिलिक फाइबर सामान्य के कम मूल्य पर नियंत्रित किया गया है:
- (ii) भारतीय उद्योग को क्षति हुई है; और
- (iii) यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण ही हुई है ।

49. प्राधिकारी पाटन मार्जिन न के बराबर या उससे कम राशि का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों की पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित, याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षतिरहित । ... से की गयी है । इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमा शुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों से होगा ।

50. प्राधिकारी कस्टम टैरिफ अधिनियम की अनुसूची -I के अध्याय 55 के उपशीर्ष 5501ण्ण30 और 5503ण्ण30 के अधीन अपने वाले ब्रिटेन, जर्मनी, बल्गारिया और ब्राज़ील ऐ एक्रिलिक फाइबर के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । यह पाटनरोधी शुल्क निम्नांकित तालिका के कॉलम 3 के अनुसार होगा :-

क्रमांक	देश	पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी (\$) डालर प्रति कि.ग्रा.
1	2	3
1.	ब्रिटेन के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.33
2.	जर्मनी के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.14
3.	बुल्गारिया के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.38
4.	ब्राजील के सभी उत्पादक/निर्यातक	1.03

51. उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी दिनांक 7. दिसंबर 2001 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुस्ति करते हैं।

52. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्याधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

एल. थी. मप्टक्रष्ण, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

Final Findings

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre originating in or exported from U.K., Germany, Brazil and Bulgaria—Final Findings.

No. 42/1/2001-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from the Forum of Acrylic Fibre Manufacturers, New Delhi on behalf of the domestic industry alleging dumping of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from UK, Germany, Brazil and Bulgaria (hereinafter referred to as subject countries);

(ii) The Authority notified the Embassies of UK, Germany, Brazil and Bulgaria in India about the receipt of petition made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub rule (5) of Rule 5 supra;

(iii) The Authority on the basis of information and evidence available before it decided to initiate anti dumping investigations against imports of subject goods from the subject country;

(iv) The Authority issued a Public Notice dated 28th August, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning imports of subject goods from subject country, falling under Heading 5501.300 & 5503.30 of Schedule I of the Customs Tariff Act.

(v) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 7th December, 2001 on anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from UK, Germany, Brazil and Bulgaria and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(vi) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;

(vii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassies of UK, Germany, Brazil and Bulgaria in New Delhi and to the Delegation of the European Commission in India.

(viii) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally on 27.03.2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(ix) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;

(x) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in these findings;

(xi) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 8.8.2002 vide a disclosure statement and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(xii) The Authority also provided an opportunity of one-to-one hearing to the Associations of the user Industry.

(xiii) The investigation covered the period from 1st April, 2000 to 31st March, 2001.

(xiv) ***** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

3. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paragraphs herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paragraphs herein below.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration in this investigation is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. All the three forms are the subject matter of this investigation. Acrylic Fibre is classified in chapter heading 55.01 and 55.03. The product is classified under 5501.30 and 5503.30 under the Customs Tariff Act at six digit levels and under 5501.3000 and 5503.3000 under ITC. The present investigations were in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Subsequent to the issue of disclosures Ludhiana Spinners Association has argued that the Authority is considering Acrylic Fibre, Tow and Tops for the investigation and the customs authorities do not consider on similar lines. The Association has further prayed that before considering all the three forms of Acrylic Fibre, the customs authorities may also confirm that Acrylic Fibre can be Acrylic Fibre, Acrylic Tow and Acrylic Top. Till such time this is done the anti-dumping duty may be

limited to Acrylic Fibre only. The Authority finds that the Ludhiana Spinners Association had not made any arguments on the product under consideration in any of their earlier submissions after initiation of investigation or after preliminary findings or after the oral hearing so that submissions made by them could be made available by the Authority to the other interested parties to offer their views or rebuttals. Therefore the Authority views that these arguments have been made at a very delayed stage. Nonetheless, the Authority holds that the arguments made by the Ludhiana Spinners Association is not acceptable and confirms the preliminary findings as regards product under consideration.

5. Like Article:

The petitioner claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. None of the interested parties who have responded to the investigation has disputed that Acrylic Fibre exported by the subject countries and Acrylic Fibre produced by the domestic industry are like article. Thus, the Authority confirms that Acrylic Fibre being produced by the domestic industry is like article to the product under consideration.

D. DOMESTIC INDUSTRY:

6. The petition has been filed by Forum of Acrylic Fiber Manufacturers, New Delhi on behalf of the domestic industry. The following producers of acrylic Fibre in India had specifically consented to participate in the present Anti-dumping investigations.

- a) Indian Acrylics Limited,
- b) Consolidated Fiber and Chemicals Limited,
- c) Pasupati Acrylon Limited,

The above-mentioned companies provided all information required for the purpose of the present investigation and had offered themselves for information and verification.

Views of Ludhiana Spinners Association:

7. It has been argued by Ludhiana Spinners Association that the production figures for the domestic industry is distorted as it does not include production of all the Indian producers.

Views of Indian Spinners Association

8. Indian Spinners Association has argued that while the petition for imposition of anti-dumping duty may be filed by the requisite percentage of the industry, the impact of imports has to be studied for all the domestic producers taken together. The method of pick and choose followed by the domestic producers is not fair and proper.

Examination by the Authority

9. The Authority finds that the share of three petitioner companies accounts for 61% of total Indian production of subject goods including the production of M/s. Vardhman Acrylics Ltd., who are an importer of subject goods. After excluding the production of M/s. Vardhman Acrylics Ltd., from the total Indian production, the share of the three petitioner companies is 73.85% of the Indian production.

10. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, “domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case (such producers shall be deemed) not to form part of domestic industry.” As the petitioners account for a major proportion of the total Indian production of subject goods, i.e. more than 50%, the Authority is of the view that the petitioners be treated as ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) supra.

E. EXAMINATION OF ISSUES RELATED TO NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

11. Views of the domestic industry

The Designated Authority sent questionnaire to the known exporters/producers in Brazil, Bulgaria, Germany and UK. A few exporters responded to the Authority. However, responses filed by all exporters are grossly insufficient and inadequate, as held by the Designated Authority in the preliminary findings. None of the exporter have furnished any additional information to the Designated Authority. Therefore, the responses of the exporters should be rejected for the final determination. The Authority would be justified in proceeding with the best available information in accordance with the Rules.

12. Views of Indian Spinners Association

Indian Spinners Association has expressed the following views:

- (i) Normal value determination on the basis of one transaction is not correct. This could be unusual transaction.
- (ii) CRFIS situated in Brussels have informed that US \$ 2.67 is price for speciality product. This information should not be rejected.
- (iii) Normal value for Germany US \$ 1.66, if found as correct then normal value in UK can not be US \$ 2.67 in any case. This shows false claim by the domestic industry.
- (iv) Normal value for Germany is also determined on the basis of one single transaction, which is not correct.
- (v) Information supplied by exporters from Bulgaria should be taken into consideration as a guideline. The cost route adopted to arrive at normal value is replete with guess work.
- (vi) As regards Brazil, there is no clue, how petitioner worked out conversion cost, power cost, labour cost and financial cost etc. and therefore the calculation of normal value should not be accepted.
- (vii) As regards export price the Authority has allowed standard adjustments on account of freight, insurance, commission, inland freight and port charges. The Authority should consider the incidence of actual costs on account of these adjustments.

13. Submissions made by Ludhiana Spinners Association:

- (i) The contention of the domestic producers regarding dumping by exporters from the four countries under reference is untenable as the goods have been supplied by the producers from these countries at the normal price. The price at which the exporters have supplied goods to importers in our country is based on their huge modern plants, cost awareness and efficiency.
- (ii) For normal value determination solitary transaction should not form the basis. The type of goods exported is also of better quality and not of normal Acrylic Fibre.
- (iii) Normal value should not be determined on the constructed cost. Authority may use services of Indian Missions in these countries

Examination by the Authority

14. Normal Value :

As brought out in the preliminary findings, the Designated Authority sent questionnaires to known exporter of the subject goods in the subject countries. The Authority had informed the Embassies of subject countries in India with a request to advise the exporters from these countries to respond to the Authority. Responses had been received from the following exporters/ exporters' organization:

- (i) Acordis UK Ltd., UK.
- (ii) M/s. Lukoil Oil Company, Bulgaria.
- (iii) DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Germany.
- (iv) Dralon GmbH – Bayerwerk, Germany.
- (v) International Rayon and Synthetic Fibres Committee
- (vi) (CIRFS), Brussels.

These responses had been dealt with appropriately at the preliminary findings stage. The Authority had informed the Embassies of the subject countries and the Delegation of the European Commission in India of the preliminary findings.

15. Subsequent to the preliminary findings following responses have been received:

- (i) M/s Lukoil Bulgaria have reiterated that their export of Acrylic Fibre to India has been done via a trader located in Great Britain who actually sold the fibres to Indian end-users at prices higher than those mentioned in their earlier response.
- (ii) M/s. Acordis UK informed that they are in the process of submitting price undertaking. However, the Authority has not received any complete price undertaking on the proforma sent to the exporter mentioning the actual export price of subject goods offered by the exporter in order to enable the Authority to take a view in the matter.
- (iii) M/s. Markische Faser AG, Germany have informed that they have closed the production of Acrylic Fibre in September 2000.
- (iv) The Embassy of the Federative Republic of Brazil has made following submissions subsequent to their disclosures:
 - a) The Government of Brazil, as an interested party in the investigation, would like to assert that the report divulged does not

contain the essential facts under judgment, which would substantiate a decision by the investigating authority. Those facts are equally absent from the report and the preliminary notification of injury, issued on December 7th 2001.

- b) Those essential facts, as per article 69 of the WTO Anti-Dumping Agreement, henceforth referred to as “WTO Agreement”, should have been determined by the Anti-dumping investigation undertaken to determine injury and causal relation.
- c) As per Article 2 of WTO Agreement, the methodology employed to determine normal value, export price and dumping margin, should have been disclosed and so should the respective elements and values.
- d) The volumes per origin and the cumulative evaluation of the effects of imports, as of convenience, are not to be found, and neither is data concerning competition between imports from different sources and the national production, as per articles 3.2, 3.3. and 5.8 of the WTO Agreement.
- e) As per article 4 of the same agreement, accurate data on the volume of production of the petitioner companies and those supporting them should have been disclosed, as well as data pertaining to factors and economic indicators relevant for the establishment of injury, in accordance with article 3.4 of the WTO Agreement.
- f) Furthermore, relevant data should have included, among others, on the following aspects:
 - (i) Production and sales of the domestic industry and of the national industry as compared to the volume of imports.
 - (ii) Patterns of apparent demand in the Indian market.
 - (iii) Evolution of the utilization of the installed capacity.
 - (iv) Price composition.
 - (v) Evolution of employment and salaries in the industry.
 - (vi) Patterns of industrial productivity.
 - (vii) Profit, investment returns and utilization of the installed capacity; factors that influence internal prices, real or potentially negative effects on liquidity, growth and capacity to increase capital and attract investments.

The mere presentation of comments, counter-arguments and rejoinders of the interested parties do not constitute, as the afore mentioned Report seems to imply, the unique essential facts as per Article 6.9 of the WTO Agreement.

The Brazilian Government sustains that there is no characterization of injury to the domestic industry by imports allegedly at dumped prices.

- (viii) It has been further argued by the Brazilian Embassy that the investigating authority has not considered the information regarding production, sales, costs of the other Indian domestic companies that did not sign the petition. Further, factors like operating conditions of the domestic industry as per the technology employed and obsolescence of equipment, capacity of domestic industry in meeting demand and evaluation of other factors other than imports have not been considered by the Authority.
- (ix) In the light of their submissions, the Brazilian Embassy has requested for closure of the investigation.

16. The Authority recalls its preliminary findings as regards normal value. None of the exporters from UK had filed complete response on the questionnaire. Only M/s. Acordis, UK had responded and had offered a price undertaking. However, the Authority has not received any complete price undertaking on the proforma sent to the exporter mentioning the actual export price of subject goods offered by the exporter in order to enable the Authority to take a view in the matter. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from UK on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. The Authority has considered the views of various interested parties as regards the basis of normal value adopted in respect of UK for the preliminary findings. The Authority finds that the domestic sales transaction relied upon for the preliminary findings for normal value determination appeared to relate to special Acrylic Fibre. The Authority has also considered the constructed cost of production for Acrylic Fibre and is of the view that this may form the basis for normal value in respect of UK and therefore normal value for UK has been determined on the basis of constructed cost of production as per information furnished by the petitioner.

17. The Authority recalls its preliminary findings on normal value in respect of Germany. No fresh evidence has been made available to the Authority. The Authority has also considered the information on constructed normal value. The Authority finds that the normal value determined, on the basis of evidence furnished by the petitioner regarding exports from Germany to a third country,

is lower than the constructed normal value. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject country in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from Germany on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority confirms the normal value as determined for the preliminary findings.

18. In respect of Bulgaria the Authority had determined the normal value for preliminary findings on the constructed cost of production as per information furnished by the petitioner. No fresh evidence has been made available to the Authority. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from Bulgaria in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from Bulgaria on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the best available information.

19. There has been no response from any exporter from Brazil at any stage. As regards the arguments put forward by the Brazilian Embassy in response to the disclosure, the Authority finds that no submissions were made by any exporter or the Brazilian Government immediately after the initiation or after notification of preliminary findings. As regards the methodology employed for determination of normal value the Authority holds the view that the disclosures issued under the Rules have clearly stated that in respect of Brazil the normal value is to be considered on the basis of constructed cost of production. This is due to the fact that none of the exporters from Brazil cooperated with the Authority in furnishing information to determine normal value. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from Brazil in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from Brazil on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the best available information.

20. Export Price:

The Authority recalls its preliminary findings as regards the export price determination. There has been no response from any exporter giving more information/ evidence regarding the export price or the adjustments allowed. The authority therefore confirms the preliminary determination of export price in respect of UK, Germany and Bulgaria. In respect of Brazil the Authority had called more information on export transactions from DGCI&S. No further transaction-wise information has been received by the Authority. The Brazilian Embassy in their comments

on disclosures has not given any information relating to export prices, etc. of the Brazilian exporter. In the absence of any fresh information relating to Brazil exports the Authority is constrained to rely upon the best available information, i.e. as per DGCI&S published data and therefore confirms the export price as determined for the preliminary findings.

21. Dumping Margin:

The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin are laid down in Annexure-I to the Rules. For the purpose of the fair comparison between the normal value and export price, the Authority has made calculations and comparisons at the same level of trade. Normal Value at ex-factory level has been compared with the export price at ex-factory level. Considering the normal value and export price, determined as detailed above, the dumping margin comes as under:

S. No.	Country	Dumping Margin %
1.	UK	26.16%
2.	Germany	10.29%
3.	Bulgaria	31.37%
4.	Brazil	185.58 %

F. INJURY AND CAUSAL LINK

22. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

- (i) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;
- (ii) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”

23. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that:

- (a) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- (b) While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

24. Views of the domestic industry:

- (i) The domestic industry suffered injury due to dumping in the investigation period from various sources including subject countries, investigation against which are either under progress or anti-dumping duty is already in force. Thus, the injury to the domestic industry is required to be seen in the light of existing duties and on-going investigations against other countries.
- (ii) The sales volume of the domestic industry, which were increasing till 1999-2000, declined in the investigation period.
- (iii) Given the level of price undercutting, the sales of the domestic industry would have declined further, had the domestic industry not compromised on the prices.
- (iv) The domestic industry is making losses year after year due to continued dumping of acrylic fibre from one after another countries, which includes subject countries also.

(v) Market share of imports from the subject countries is significant. The share has increased over the years.

(vi) The productivity of the domestic industry declined in the investigation period due to steep decline in the production, in spite of reduction in the number of employees.

(vii) The return on investment for the domestic industry continues to remain negative in spite of imposition of anti dumping duty on a number of sources.

(viii) The return on investment declined significantly in the investigation period due to heavy losses faced by the domestic industry in this period.

(ix) The capacity utilization has declined very significantly in the investigation period due to decline in production.

(x) The landed value of imported material from a number of countries is significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price undercutting.

(xi) The landed value of the imported material is below cost of production of the domestic industry causing severe price suppression and depression.

(xii) The dumping margin from the subject countries are not only more than de-minimus but also very significant.

(xiii) The cash flow was negative in 98-99, which became positive in 99-00. However, the cash flow was again negative in 2000-01.

(xiv) The level of stocks with the domestic industry increased sharply in spite of reduction in production by the domestic industry.

(xv) The domestic industry has no other option but to increase the wages for the employees due to the prevailing regulations.

(xvi) The domestic industry has enhanced capacity by debottlenecking in an effort to reduce the incidence of fixed costs. However, this has also not helped the domestic industry in reducing the losses.

(xvii) The constituents of domestic industry had to undergo financial restructuring some time back with lot of difficulties. The financial

institutions are not willing to lend funds to the domestic industry due to continued losses.

(xviii) Dumping from Bulgaria, Brazil, Germany and UK has resulted in injury to the domestic industry.

(xix) The final duties may also be recommended in terms of US \$ only (in fixed amounts), so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate.

25. Views of Indian Spinners Association:

(i) Injury should be seen for Indian industry as a whole and not for the petitioners.

(ii) The domestic industry should provide information with regard to all producers. Method of pick and choose is not just and fair.

(iii) Production and market share of domestic producers increased as per data of the office of Textiles Commissioner.

(iv) Capacity and its utilization has increased, hence, there is no injury to the domestic industry.

(v) Cost of production of the domestic industry increased by 38% whereas selling price increased by 41 %.

(vi) There is no dumping and no injury.

(vii) The injury to the domestic industry if any is due to lack of cost consciousness, insufficient scale of production, lack of R&D and poor working.

26. Views of Ludhiana Spinners Association

(i) We are largest consumer of acrylic fibre in the country, however, no notice has been served to us before imposition of provisional duty.

(ii) 14 countries are attracting Anti Dumping Duty at present. No other textile product attracts Anti Dumping Duty from so many sources.

(iii) This is an attempt of the domestic industry to cover their mismanagement, inefficiency and ultimate aim is to create monopoly in the Indian market.

- (iv) Production figures of the domestic industry is distorted as it does not include production of all Indian producers.
- (v) Production of the Industry has gone up by 29% over previous year.
- (vi) Injury due to cyclone in Gujarat and earth quake in Gujarat is the reason behind injury if any.
- (vii) Injury is due to reduction in customs duty in budget and not imports.
- (viii) None of the domestic producers stated in their balance sheet that their profitability is lower due to dumping from newer sources.
- (ix) The industry has old and outdated machinery, which is resulting into injury to the industry.
- (x) The industry is not able to meet the present demand and future demand.

27. Views of M/s Lukoil, Bulgaria

The result of the preliminary investigation makes it evident that our market share is only 3%, which can not possibly affect the interests of the Indian producers. Neither can it have any influence on price levels for the aforesaid market.

Examination of Injury and Causal Link by the Authority:-

28. The Authority recalls its preliminary findings regarding injury analysis. The domestic industry has furnished information on various economic factors/indices relating to injury determination, viz., natural and potential decline in sales, profits, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity, factors affecting domestic prices, profitability, return on investments, effects on cash flow, employment, wages, etc. The Authority has taken into account the aforesaid indices regarding injury while doing the final determination. The Authority has examined the submissions made by various interested parties, viz., domestic industry, exporters, Indian Spinners Association, Ludhiana Spinners Association and the Brazilian Embassy. The Authority is of the view that all the relevant

indices as per Annexure II of the Rules have been examined in respect of the domestic industry for this investigation. While the Authority has examined all parameters mentioned in Annexure II of the Rules, however, some of the relevant parameters, which show injury, are discussed in detail as under:

29. As regards volume of imports The Authority has examined the information regarding the volume of exports from the subject country during the period of investigation and the preceding years. During the POI the imports from the four subject countries taken together were of 4195 MT. During the year 1999-2000 these imports were 2469 MT and 3739 MT during 1998-99 (as per DGCI&S data). These imports account for a market share of 3.35% in 1998-99, 2.18% in 1999-2000 and 3.73% during 2000-01. When compared to the previous year 1999-2000 the share in the market had shown an appreciable increase during the POI. However, in volume terms the imports from the subject countries during POI showed an increase of 69% over the imports in the previous year. The increase in market share though not very significant is however appreciable and the increase in imports in absolute terms does hold a threat for the domestic industry. The Authority has found that there has been an increase in the dumped imports in absolute terms.

30. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price under-cutting by the dumped imports. The landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization. The imports were having significantly suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price to earn a reasonable return in view of the dumped imports.

31. The capacity utilization of the domestic industry has declined from 93.07% in 1999-2000 to 84.03% in the investigation period due to decline in production. The installed capacity of the three petitioner companies had increased during the POI. However, the total production of the petitioner companies declined during the POI in comparison to the previous year. The production of the two other domestic producers, who have supported the

petition but have not participated in the present investigation, may have increased during the POI. The argument of the Indian Spinners Association is that the production of Acrylic Fibre has increased during POI. The petitioner companies account for 61% share, i.e. a major proportion of the domestic production of the subject goods during the POI and have been construed as 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) supra. Therefore, the Authority holds the view that the domestic industry has suffered injury on account of decline in production and capacity utilization.

32. Till 1999-2000, sales volume of the domestic industry has been increasing. However, sales volume declined from 70591 MT in 1999-00 to 59119 MT in the investigation period i.e. by 16.25% in comparison to the previous year. Further, the domestic industry has been selling its material at a price, which do not permit recovery of even cost of production.

33. Since last few years, the domestic industry has not been able to make profits due to dumping of the product from one after another countries, which includes subject countries also. The losses of the domestic industry steeply increased in the investigation period from -100 (indexed) in 1997-98 to -373 (indexed) in the investigation period.

34. The productivity per employee declined in comparison to previous year, in the investigation period due to steep decline in the production, in spite of reduction in the number of employees.

35. The return on investment declined in the investigation period due to losses faced by the domestic industry in this period. The return on investment for the domestic industry continues to remain negative in spite of imposition of anti dumping duty on a number of sources.

36. The cash flow was negative in 98-99 which became positive in 99-00 . However, the cash flow was again negative in the investigation period.

37. The level of stocks with the domestic industry increased during POI in comparison to previous year in spite of reduction in production by the domestic industry.

38. The domestic industry is being forced to resort to curtailment of employment due to continued financial losses and negative cash flow.

39. Due to the prevailing regulations, the domestic industry has to increase the wages causing further impact on profits.

40. Enhancement of capacity by de-bottlenecking with a view to reduce the incidence of fixed costs has not helped the domestic industry during the period of investigation.

41. All above parameters cumulatively show that the domestic industry has suffered material injury from the dumping of subject goods from subject countries.

42. Cumulative assessment of injury

As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article --- and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods from subject countries on the domestically produced like article and has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods on the domestic industry.

43. While determining the non-injurious price for the like article for the domestic industry, the Authority considered the optimum cost of production for the domestic industry taking into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials during the POI which went into the production of the product under consideration. Also, while arriving at the injury margin, the Designated Authority took into account optimum capacity utilization for arriving at a fair selling or non-injurious price. The Authority has carried out a detailed examination of the domestic industry to arrive at non injurious price. While arriving at non injurious price, the Authority has done appropriate analysis of the relevant factors such as usage of raw material and utilities, expenses incurred by the domestic industry during the

period of investigation. Verification at premises of the domestic industry has been done to the extent required.

Causal Link :

44. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

45. The Authority has examined all the relevant indices. Volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms. The dumped imports have led to a significant price under-cutting effect on the domestic industry's product. Due to the landed value of the dumped imports the domestic industry has been selling its material at a price, which do not permit recovery of even cost of production. The domestic industry has not been able to realize a fair selling price on its product due to the dumped imports resulting in financial losses. The domestic industry has made losses. The return on capital investment has become negative. The industry is having negative cash flow. Unsubstantiated claims have been made by some interested parties that injury caused to the domestic industry is due to other factors like poor R&D, inefficiency etc. The Authority does not find any merit in these arguments. The Authority has thus come to conclusion that material injury has been caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject countries. Subject to these the Authority confirms the preliminary findings as regards injury and causal link.

G. INTEREST OF INDIAN INDUSTRY AND OTHER ISSUES:

46. It has been argued by some of the importers and users that the interest of the users of Acrylic Fibre should be taken into account while imposing anti dumping duty. They have requested to reconsider the imposition of anti

dumping duty on Acrylic Fibre since the threat of imports serves as a check on the prices of the local producers.

47. In this context the Authority reiterates its preliminary findings wherein it is stated that the purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using Acrylic Fibre and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

H. FINAL FINDINGS

48. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that :

- (i) Acrylic Fibre has been exported to India from subject countries below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered injury;
- (iii) The injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

49. The Authority proposes to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed price of imports has been compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation. Landed value of imports for the purpose has been determined as the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

50. The Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty on all imports of Acrylic Fibre from UK, Germany, Bulgaria and Brazil falling under Sub Heading 5501.30 and 5503.30 of chapter 55 of Schedule I of Customs Tariff Act . The anti dumping duty shall be as in Col 3.in the following table:

Sl.No	Country	Anti Dumping Duty US \$ per Kg
(1)	(2)	(3)
1.	All producers/exporters from UK	0.33
2.	All producers/exporters from Germany	0.14
3.	All producers/exporters from Bulgaria	0.38
4.	All producers/exporters from Brazil	1.03

51. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 7th December, 2001.

52. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority